# निजी आईटीआई की होगी निगरानी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

श्रम संसाधन विभाग अब निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कामकाज की निगरानी करेगा। उनकी अनियमितता से संबंधित सभी शिकायतों की जांच होगी। छात्रों से मनमानी फीस वसूली रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। विभाग के प्रधान सचिव सुभाष शर्मा ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2014 में 105 नये सरकारी आईटीआई खोले जाने हैं। इसकी स्थापना में 559 करोड़ खर्च होंगे। विभाग ने 14वें वित्त आयोग को वर्ष 2014-15 के लिए 635 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। सूबे के दस नियोजनालयों का पूर्णतः आधुनिकीकरण किया जायेगा। इसमें 69.15 करोड़ खर्च होंगे।

एक प्रश्न पर उन्होंने माना कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण अधिकतर जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं है। इसका कारण यह है कि बीमा कंपनियों के पिछले इकरारनामे की अवधि पूरी हो चुकी है। नए अनुबंध के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। एक कंपनी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से टेंडर में तथ्यात्मक चूक होने व कोर्ट के स्टे आर्डर के कारण जिलों में यह योजना बंद है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि जनवरी माह के दूसरे सप्ताह तक अदालत का फैसला आ जायेगा।

**1810 नये कौशल विकास केन्द्र खुलेंगे**

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष सूबे में 1810 नये कौशल विकास केन्द्र भी खोले जाएंगे। समुद्रपार नियोजन ब्यूरो का मामला धरातल पर सरकारी स्तर से संभव नहीं है। इसे बंद करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। कदाचार और प्रश्नपत्र लीक होने के कारण आईटीआई की रद्द विषयों की समय पर पुनर्परीक्षा नहीं हो सकी। अब ये परीक्षाएं 21 जनवरी से होंगी।